झांसी में बनेगा नया औद्योगिक नगर

नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : डिफेंस कारिडोर के बाद बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले एक और निर्णय पर अंतिम मुहर लग गई है। योगी सरकार नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड के झांसी जिले में नया औद्योगिक नगर विकसित करेगी। परियोजना के पहले चरण में झांसी के 33 राजस्व गांवों की 35,000 एकड़ (14,000 हेक्टेयर) जमीन अधिग्रहीत की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में झांसी के इन 33 गांवों को शामिल करते हुए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय झांसी में होगा। इस निर्णय से बुंदेलखंड के जिलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकेगा और अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ यहां बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण/नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नोएडा की तर्ज पर एक नया औद्योगिक नगर विकसित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1976 में नोएडा प्राधिकरण के गठन के 47 वर्षों बाद राज्य सरकार ने एक नए औद्योगिक नगर की स्थापना का निर्णय लिया है।

मंगलवार को मंत्री परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना • जागरण

कैबिनेट के अन्य फैसले

- आकांक्षी नगर योजना से 100 छोटे शहरों का होगा विकास
- पुलिस विभाग में निर्माण के लिए 3109 करोड़ रुपये स्वीकृत
- निजी हाथों में सौंपे जाएंगे घाटे में चल रहे 12 पर्यटक आवास गृह
- गुड़-खांडसारी इकाइयों के लिए 10% वृद्धि के साथ समाधान योजना को स्वीकृति

धान का समर्थन मूल्य 143 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा

कैबिनेट ने धान क्रय नीति को स्वीकृति प्रदान की। धान के समर्थन मूल्य में 143 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सामान्य धान की खरीद 2,183 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से की जाएगी, जबकि ग्रेड ए के लिए 2,203 रुपये का भाव दिया जाएगा। देखें >> 2

खन्ना ने बताया कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में पहले चरण में झांसी-ग्वालियर रोड और झांसी-बबीना-ललितपुर रोड के बीच पड़ने वाले 33 राजस्व ग्रामों की 35,000 एकड़ भूमि अर्जित कर औद्योगिक शहर की स्थापना की जाएगी। इसमें से लगभग 8,000 एकड़ भूमि ग्राम समाज की है। ग्राम समाज की भूमि का पुन्ग्रहण कर उसे निश्शुल्क बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं किसानों की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। जिलाधिकारी झांसी की ओर से उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के अनुसार निजी भूमि का अनुमानित मूल्य 6,312 करोड़ रुपये है।

प्रस्तावित नए औद्योगिक नगर में उद्योगों के साथ शैक्षणिक व अन्य सेक्टर्स से संबंधित संस्थाओं के विकास, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व आवासीय परिसर के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित नए औद्योगिक नगर में विश्वस्तरीय नियोजन व उसके अनुसार अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झांसी के अलावा बुंदेलखंड के अन्य जिलों में भी सैटेलाइट औद्योगिक क्षेत्र के विकास में सहायक होगा। झांसी ईस्ट-वेस्ट, नार्थ साउथ स्वर्णिम चतुर्भुज कारिडोर का जंक्शन है और यह प्रदेश को देश के दक्षिणी हिस्से से जोड़ने का रास्ता भी है। झांसी में एयरपोर्ट का निर्माण भी प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुपूरक बजट में नई मांग के रूप में 'मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण/नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना को शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के लिए 5,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण/नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना मद के तहत ऋण के रूप में 5000 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत टाउनशिप समेत औद्योगिक स्थापना के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं का यहां समावेश होगा। इसके गठन से झांसी और आसपास क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। जन सामान्य को विकास के साथ ही रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जिसका प्रत्यक्ष लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर का आकार देने का जो लक्ष्य तय किया है, उस संकल्प की सिद्धि में भी यह सहायक होगी।